



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, वीरवार, 31 दिसम्बर, 2009 / 10 पौष, 1931

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं विद्युत विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला-2, 21 दिसम्बर, 2009

**संख्या विद्युत-छ-(5)-42/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल सियूं, उप तहसील नौहरा, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं० 103, शिमला-3, जिला शिमला, हि० प्र० में किया जा सकता है।

#### विवरणी

जिला	उप तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
सिरमौर	नौहरा	सियूं	440 / 297 / 214	02-00
			3	11-11
			265	04-03
			3 / 1	08-10
			कुल कित्ता-4	रकबा 26-04 बीघा

शिमला-2, 21 दिसम्बर, 2009

**संख्या विद्युत.-छ-(5)-54/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल अकावाली (बद्दी) तथा ढैला, तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि०प्र० में 66 के० वी० संचार लाईन HPSIDC औद्योगिक क्षेत्र, दबनी के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव: एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचू ना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तम भवन, शिमला-4 के कार्यालय में किया जा सकता है।

#### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकवा (बीघों में)
सोलन	बद्दी	अकावाली (बद्दी)	445/1	0-4
			291/1	0-4
		ढैला	675/1	0-4
			616/1	0-4
			488/1	0-4
			कुल कित्ता-5	कुल रकबा- 1-00 बीघा

**संख्या विद्युत-छ-(5)-55/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल काठा तथा भटोलीकलां तहसील बद्दी, जिला सोलन, हि0प्र0 में 66 के0 वी0 संचार लाईन HIMUDA औद्योगिक क्षेत्र, भटोलीकलां के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव: एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि के रेखांक का निरीक्षण भू-अर्जन समाहर्ता हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तम भवन, शिमला-4 के कार्यालय में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
सोलन	बद्दी	काठा	242/1	0-4
		भटोलीकला	171/1	0-4
			131/1	0-4
			144/1	0-4
		कुल कित्ता-5	कुल रकबा-	0-16 बीघा

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 2009

**संख्या विद्युत-छ-(5)-40/2008.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी0सी0) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल जैयचा मझाई, उप-तहसील ददाहु, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव: एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-6 के उपबन्ध के अधीन सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के लिए यह घोषणा की जाती है और उक्त अधिनियम की धारा-7 के उपबन्धों के अधीन भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, शिमला-3, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश को एतद्वारा भूमि के अर्जन के लिए आदेश लेने का निर्देश दिया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा-17 की उप धारा-1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अत्याधिक आवश्यक मामला होने के कारण भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं० 103, शिमला-3, जिला शिमला, हि० प्र० उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन नोटिस के प्रकाशन के 15 दिन की अवधि समाप्त होने पर पंचाट देने से पूर्व भूमि का कब्जा ले सकते हैं।

4. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, थिसिल बैंक भवन, शिमला-3, जिला शिमला, हि० प्र० में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	उप-तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
सिरमौर	ददाहु जैयचा	मझाई	27	0-10
			40	0-3
			147	0-6
			155	0-9
			156	0-3
			188	0-4
			184	0-15
			214	0-16
			223	1-7
			9	0-16
			17	1-0
			21	0-9
			77	0-10
			126	0-8
			127	0-9
			134	0-3
			146	0-19
			160	0-4
			163	0-13
			164	1-7
			191	0-18
			209	0-13
			211/1	0-12
			217	0-12
			365	1-15
			204	0-13
			225	0-6
			144	0-19
			145	1-13
			211	0-6
			245	0-7
			10	1-9
			31	1-5
			138	1-9
			141/1	0-1
			150	0-9
			161	0-3
			168	0-4

---

192	1-3
193	0-17
195	0-13
200	0-19
210	0-10
212	0-13
216	0-16
222	1-7
246	0-3
363/1	0-15
141	0-5
43	0-6
132	0-16
175	0-12
178	0-8
37	0-2
242	0-9
137	1-0
162	0-17
190	0-8
190/1	0-4
364	3-11
367	2-17
11	1-5
18	0-4
48	0-11
78	0-6
83	0-5
143	1-8
149	0-6
170	1-9
176	0-4
179	0-10
183	0-16
232	1-0
235	2-9
84	0-5
35	-18
366	1-0
237	2-13
42	0-4
12	2-1
117/1	0-17
73	0-10
128	3-5
106	0-14
13	0-13
3	1-4
4	0-14
30	0-18
32	1-8
33	0-7

---

34	0-8
39	0-3
92	1-7
140	0-4
142	0-2
148	0-2
151	0-7
152	0-1
153	0-12
154	0-1
171	2-8
198	0-4
201	0-1
251	0-7
250	0-12
221	0-5
227	0-6
228	0-18
165	3-15
101	0-7
74	0-1
86	0-10
89	0-3
104	1-7
118	0-12
94	0-18
199	0-13
236	1-13
23	0-8
87	1-9
88	0-4
202	0-2
107	0-18
108	0-10
173	6-4
187	0-6
521/115	1-9
218	1-0
113	1-2
520/115	0-14
122	0-18
131	0-4
357	2-7
79	1-1
182	1-5
136	0-5
41	0-10
91	0-5
93	0-13
224	0-15
102	0-12
238	1-17

---

20	1-11
166	2-2
358	5-2
369	3-13
370	1-8
359	3-0
364/1	0-12
371	0-16
16	0-10
7	1-11
15	1-1
28	0-12
46	2-3
85	0-9
203	0-13
8	0-6
29	0-4
6	1-9
139	0-8
159	0-6
239	0-15
240	0-14
241	0-4
14	1-19
25	0-15
97	0-4
98	3-3
99	0-2
100	0-19
103	0-14
105	0-16
109	0-15
110	1-4
111	0-3
121	0-15
112	1-15
114	2-0
123	0-10
124	1-3
116	0-8
117	1-2
119	0-11
120	0-13
157	0-6
158	0-11
47	0-12
135	0-13
194	0-5
196	0-17
197	0-16
44	0-8
38	0-8

19	0-13
22	0-3
45	0-11
181	0-13
522/256	2-15
231	2-11
80	0-13
81	0-10
82	0-8
167	3-0
169	0-5
180	0-7
185	0-9
186	1-4
219	1-19
220	0-3
229	1-5
233	0-12
234	0-10
215	2-5
207	0-5
95	0-17
96	1-7
26	0-13
177	1-2
243	0-18
49	1-6
75	0-11
189	0-15
174	1-3
205	0-15
213	0-13
244	0-11
206	1-0
208	0-17
24	1-2
5	4-11
230	0-16
523/256	5-10
226	0-9
342	0-2
254	2-1
<hr/>	
कुल कित्ता-236	कुल रकबा-219-1 बीघा

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 2009

**संख्या विद्युत-छ-(5)-52/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल लाना माड़ग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि0प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह



अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं० 103, शिमला-3, जिला शिमला, हि० प्र० में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
सिरमौर	पच्छाद	लानामाड़ग	7	2-0
			81	4-8
			82	4-5
			76	2-3
			262/231	19-19
			263/231	13-8
			83	1-12
			145/131	12-13
			कुल कित्ता-8	कुल रकबा - 60-8 बीघा

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 2009

**संख्या विद्युत-छ-(5)-52/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल छपांग, तहसील पच्छाद, जिला सिरमौर, हि० प्र० में रेणुका बांध के निर्माण व इसके जलमग्न क्षेत्र हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला-3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

### विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
सिरमौर	पच्छाद	छपांग	94/2/1	7-16
			95/2/1	4-8
			96/2/1	13-2
			80/1	1-1
			135./66/1	19-11
			70	5-19
			74	1-1
			79/1	1-16
			137/71	2-5
			134/66	15-0
			72	1-6
			73	5-7
			136/71	0-6
			83/1	0-6
			कुल कित्ता-14	कुल रकबा - 79-4 बीघा

शिमला-2, 23 दिसम्बर, 2009

**संख्या विद्युत-छ-(5)-56/2009.**—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड जो कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का पहला अधिनियम) की धारा-3 के खण्ड (सी.सी.) के अन्तर्गत सरकार के स्वामित्व और नियन्त्रण के अधीन एक निगम है के द्वारा अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः मुहाल चूली ददाहू, उप तहसील ददाहू, जिला सिरमौर, हि0 प्र0 में रेणुका बांध के निर्माण व इसके भवन निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएवः एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इससे सम्बन्धित हैं या हो सकते हैं की जानकारी के लिए भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्यधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा (4) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

5. भूमि से सम्बन्धित रेखांक का निरीक्षण, कार्यालय भू-अर्जन समाहर्ता, हिमाचल प्रदेश विद्युत निगम, उत्तम भवन, नजदीक सुरंग नं0 103, शिमला-3, जिला शिमला, हि0 प्र0 में किया जा सकता है।

विवरणी				
जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	रकबा (बीघों में)
सिरमौर	ददाहू	चूली ददाहू	350/1	1-12-11
			349/1	1-16-9
			348/1	0-13-14
			347/1	0-13-11
			345/1	0-1-12
			कुल कित्ता-5	कुल रकबा 4-17-17

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित /—  
प्रधान सचिव।

-----

**SPECIFIC NOTIFICATION  
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH  
FINANCE DEPARTMENT**

**NOTIFICATION**

*Shimla-2, 31st December, 2009*

**No. Fin-2-C(5)-9/2008.**—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of imachal Pradesh Government Stock (securities) of 10-year tenure for an aggregate amount of **Rs. 100.00 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the revised General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003 dated 20th July, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

**Object of the loan**

1. (i) The proceeds of the State Government Securities will be utilized for the development programme of the Government of Himachal Pradesh.

(ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293 (3) of the Constitution of India.

**Method of Issue**

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No.Fin-2-C(12)-11/2003, dated 20-7-2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the yield based auction under multiple price format.

**Allotment to Non-Competitive Bidders**

3. The Government Stock up to 10% of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1% of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure-II).

**Place and Date of Auction**

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **January 5, 2010**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Negotiated Dealing System (NDS) as stated below on January 5, 2010.

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10.30 A.M. and 12.30 P.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Negotiated Dealing System (NDS) between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

**Result of the Auction**

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **January 6, 2010**.

**Method of Payment**

6. Successful bidders will make payments on **January 6, 2010** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai(Fort)/New Delhi.

**Tenure**

7. The Stock will be of ten-year tenure. The tenure of the Stock will commence on **January 6, 2010**.

**Date of Repayment**

8. The loan will be repaid at par on **January 6, 2020**.

**Rate of Interest**

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the stock sold at the auction. The interest will be paid on **July 6 and January**.

**Eligibility of Securities**

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of  
the Governor of Himachal Pradesh.

Sd/-  
Principal Secretary.

## **Revised scheme for Non-Competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities (Annex-II of the General Notification)**

### **I. Objective**

With a view to encouraging wider participation and retail holding of Government securities, it is proposed to allow participation of eligible individuals and institutions on “non-competitive” basis in the auctions of State Government securities. Accordingly, non-competitive bids up to 10 percent of the notified amount will be accepted in the auctions of State Government securities. The reserved amount will be within the notified amount.

### **II. Eligibility**

Participation on a non-competitive basis in the auctions of State Government Securities will be open to investors who satisfy the following:-

(i) do not maintain current account (CA) or Subsidiary General Ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India.

**Exceptions.**—Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks shall be covered under this scheme in view of their statutory obligations.

(ii) make a singly bid for an amount not more than 1 percent of notified amount (face value) per auction.

(iii) Submit their bid through any one bank or PD offering this scheme.

**Exceptions.**—Regional Rural Banks (RRBs) and Cooperative Banks that maintain SGL account and current account with the Reserve Bank of India shall be eligible to submit their non competitive bids directly.

### **III. Coverage**

Subject to the conditions mentioned above, participation on “non competitive” basis is open to any person including firms, companies, corporate bodies, institutions, provident funds, trusts and any other entity as may be prescribed by RBI. The minimum amount for bidding will be Rs. 10,000 (face value) and thereafter in multiples of Rs. 10,000 as hitherto for investment in State Government securities.

### **IV. Other operational Guidelines.**

1. It will not be mandatory for the retail investor to maintain a Gilt Account (under Constitution Subsidiary General Ledger (CSGL) facility) with the bank or PD through whom they wish to participate. However, an investor can make a single bid under this scheme. An undertaking to the effect that **the investor is making** only a singly bid will have to be obtained and kept on record by the Bank or PD.
2. Each Bank or PD on the basis of firm orders received from their constituents will submit a single consolidated non-competitive bid on behalf of all its constituents in electronic format on the Negotiated Dealing System (NDS) except in extraordinary

circumstances such as general failure of NDS system, noncompetitive bid in physicals form will not be accepted.

3. Allotment under the non-competitive segment to the bank or PD will be at the weighted average rate of yield/price that will emerge in the auction on the basis of the competitive bidding. The securities will be issued to the bank or PD against payment on the date of issue irrespective of whether the bank or PD has received payment from their clients.
4. In case the aggregate amount of bid is more than the reserved amount (i.e., 10 percent of notified amount), pro rata allotment would be made. In case of partial allotments, it will be the responsibility of the bank or PD to appropriately allocate securities to their clients in a transparent manner.
5. In case the aggregate amount of bids is less than the reserved amount, the shortfall will be taken to competitive portion of the notified amount.
6. Security would be issued only in SGL form by RBI. RBI would credit either the main SGL account or the CSGL account of the bank or PD as indicated by them. The facility for affording credit to the main SGL account is for the sole purpose of servicing investors who are not their constituents. Therefore, the bank or PD would have to indicate clearly at the time of tendering the noncompetitive bids the amounts (face value) to be credited to their SGL account and the CSGL account. Delivery in physical form from the main SGL account permissible at the instance of the investor subsequently.
7. It will be the responsibility of the bank or the PD to pass on the securities to their clients. Except in extraordinary circumstances, the transfer of securities to the clients shall be completed within five working days from the date of issue.
8. The bank or PD can recover up to six paise per Rs. 100 as brokerage/commission/service charges for rendering this service to their clients. However, such costs may be recovered and accounted for separately from the clients and should not be built into the price. In case the transfer of securities is effected subsequent to the issue date of the security, the consideration amount payable by the client to the bank or PD would also include accrued interest from the date of issue.
9. Modalities for obtaining payment from clients towards cost of the securities, accrued interest wherever applicable and brokerage/commission/service charges may be worked out by the bank or PD as per agreement with the client. It may be noted that no other costs such as funding costs should be built into the price or recovered from the client.
10. Banks and PDs will be required to furnish information relating to operations under the Scheme to the Reserve Bank of India (Bank) as may be called for from time to time within the time frame prescribed by the Bank.

#### V. Review of the Scheme

The foresaid guidelines are subject to review by the Bank and accordingly, if and when considered necessary, the Scheme will be modified in consultation with the State Governments.